संपादकीय

‘किसानों के आंदोलन को समझना’

इसके लिऐ किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है कि किसानों के मुद्दों पर अर्थशास्त्रियों की टिप्णीयां अब दुखदाई स्थिति तक पहुंच चुकी हैं। जिस सलाहकार से सलाह मांगी जाऐ जब वह इतना कठोर हो जाऐ कि कहने लगे कि किसानों का आंदोलन राजनैतिक है और अपने कथन को सही ठहराने के लिऐ बोले कि किसानों की आत्महत्याओं में कमी हो रही है और किसानों की समृद्धी बढ़ रही है, तो ऐसे में कोई चुप कैसे बैठ सकता है।

किसानों की आत्महत्याओं में कमी के आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाता है, जबकि उन्हीं आंकडों से साबित होता है कि व-र् 2015 में इनमें 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। व-र् 2014 के बाद किसानों की आत्महत्याओं की संख्या को कृ-ि श्रम से अलग कर दिया गया है और इसीलिऐ आत्महत्या के आंकडे भी अलग दिखाऐ जा रहे हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उडीशा जैसे कई राज्य किसानों की आत्महत्याओं का रिकॉर्ड नहीं देते हैं। किसानों की आत्महत्याओं के आंकडे अविश्सवनीय ही रह जाते हैं, उदाहरण के लिऐ भूमि सामान्यतः आदमी के नाम पर पंजीकृत होती है तो जब कोई महीला किसान आत्महत्या करती है तो उसे किसान नहीं माना जाता।

यह एक तीखा व्यंगय है कि किसानों को कहना की न्यूनतम समर्थन मूल्य, सी.पी.आई. और डब्ल्यू. पी.आई. बदल रहे हैं, तथा किसानों की आय दोगुनी हो रही है और आत्महत्याओं में कमी आ रही है। वर्तमान किसान आंदोलन का मूल कारण कृ-ि उत्पादों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलना है। सरकार द्वारा अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य घो-ित करना ही प्र्यापत नहीं है। कुछ फसलों के लिऐ ही समर्थन मूल्य दिया जाता है, लेकिन उनमें से भी दो-तिहाई फसलें घो-ित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बिकती हैं, और पिछले व-र् की तुलना में किसानों को अधिक हानि हो रही है, यही वास्तविकता है। 80 प्रतिशत से अधिक कृ-ि फसलें समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं खरीदी जाती। सब्जियों के भाव भी आधे रह गऐ हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घो-णा पत्र में वादा किया था कि एम.एस. स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे जिसके अधीन फसल की उत्पादन लागत और 50 प्रतिशत का लाभ किसानों को दिया जाऐगा, लेकिन सरकार ने चुपचाप उच्चतम न्यायालय में ऐफिडेविट दे दिया कि वह इस रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकती। किसान इस सरकार के प्रति अपनी आशा और विश्वास खो रहे हैं, जैसा कि पहले की सरकारों ने विश्वास खोया था और अपने वादे लगातार तोडती रही।

पिछले व-र् महारा-ट्र में किसानों ने मजबूर होकर रू. 16 प्रति लिटर की दर से दूध बेचा, जबकि इसका अन्य राज्यों में औसत मूल्य रू. 35 प्रति लिटर था। अधिकतम किसान पशु रखते हैं और दूध का मूल्य कम मिलने के कारण वे पशु पालते थे, लेकिन सरकारी नीति ने घी के आयात की

नीति से इसको भी हानि पहुंचाई और गो-मांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और भैंस की बिक्री के लिऐ सीमा क्षेत्र निर्धारित कर दिऐ हैं। प्रत्येक किसान को नकद हानि हो रही है। इन सभी कारणों से किसानों की कुंठा बढ़ी जिसका विस्फोट होना निश्चित था।

एक दशक की गलत नितियों के बाद महारा-ट्र में किसान आंदोलन तो होना ही था, लेकिन मध्य-प्रदेश में भी किसान आंदोलन होना बहुत आश्र्चयजनक है, जहां के किसान दोहरे अंकों में वृद्धि दर प्राप्त कर रहे थे और अब उस राज्य में लगभग सभी कृ-ि क्षेत्रों में मंदी देखने में आ रही है। अर्थशास्त्रीयों का कृ-ि क्षेत्र में कुछ भी दांव पर नहीं लगा हुआ, इस कारण वे कृ-ि सकल घरेलू उत्पाद और कृ-ि उत्पादन की वृद्धि का ढ़िंडोरा पिटकर किसानों की समृद्धि का ब्यान कर रहे हैं और किसान आंदोलन को राजनैतिक कहकर अपने आप को बचा रहे हैं। उत्पादन बढ़ने का अर्थ यह नहीं कि किसानों की आय भी बढ़ी। इसके विपरित जब उत्पादन अधिक होता है, तो किसान को ही अधिक हानि उठानी पढ़ती है। किसान आंदोलन नोटबंदी अथवा कृ-ि अपस्फीति या गरीबी के बारे में नहीं है, यह केवल किसानों की आकांक्षाओं पर खरा न उतरने के बारे में है, क्योंकि किसान देख रहे हैं कि अन्य सभी वर्गों के लोग उनके परिश्रम पर अधिक लाभ और प्रगति कर रहे हैं, जबकि स्वंय किसानों का जीवन स्तर बद्तर होता जा रहा है। बढ़े-बढ़े विद्वान भी जान बूझकर मुद्रा स्फीति और भारत की अर्थव्यवस्था में किसानों के योगदान को नजरअंदाज कर रहे हैं और किसानों के संकट को वे समझ ही नहीं पाते।

किसान आंदोलन से यह बात समझ आ रही है कि मोदी राज के पिछले 3 व-ों में उनकी स्थिति कैसी हो चुकी है। पिछली ऐन.डी.ऐ. सरकार ने बढ़े जोरशोर से 'शाईनिंग इंडिया' अभियान को बार-बार दोहराया जो कि पूरी तरह से ून्य साबित हुआ।

कृ-ि क्षेत्र में अवयवस्था मोदी राज की देन नहीं है, किंतु उनसे बहुत आशाऐं थी कि वे किसानों की मुसिबतों को दूर करेंगे। अब गैर कृ-ि रोजगार की उम्मीदें और अच्छे दिन की उम्मीद समाप्त होती जा रही है, और श्रीमान मोदी भी कृ-ि सुधारों के प्रति अपने मनोबल को खोते जा रहे हैं, इस कारण उन्हें भी यू.पी.ऐ. सरकार की तरह लोक-लुभावन घो-णाओं तक ही सीमित रहना होगा।

सबसे बढ़ा मुद्दा यह नहीं है कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, बल्कि आंदोलन करने के बाद भी उनकी समस्याओं को कोई ठोस समाधान क्यों नहीं हो पाता। कृ-ि क्षेत्र पर निर्भर सभी वर्गों के प्रतिनिधियों की न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के मांग है, न ही कर्ज माफी की। कृ-ि कामगारों की मांग कभी नहीं बढ़ी और इस कारण किसान आंदोलन सफल नहीं हो पाते। किंतु पहली बार किसान आंदोलन में शिक्षित युवा भी कूदे हैं और इस मुहिम में अपने परिवार के सदस्यों को भी ामिल कर रहे हैं। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किन्हीं राजनेताओं या किसी नेता द्वारा नहीं किया जा रहा। वास्तव में गैर संगठित किसान इकट्ठे हो चुके हैं और ऐसा प्रभाव दिखा चुके

हैं जो संयुक्त रूप से विपक्षी दल भी नहीं कर पाते, इस कारण सरकार को घुटने टेकने पड़े। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि किसानों ने यह दिखा दिया है कि वे अपने बल पर ऐसा कर सकते हैं।

किसानों के ऋण माफ करने से ही कोई भी कमजोर सरकार विमुख किसानों के असंतो-ा को दूर नहीं कर सकती, किंतु केवल उनकी अनिश्चित्ता को कुछ समय के लिऐ टाल सकती है। जिंसों के अंतर्रा-ट्रीय मूल्य कपास और मक्का के मूल्य भी आने वाले फसल मौसम में कम हो रहे हैं, ये सभी मुद्दे ही अगले किसान आंदोलन भाग-2 के प्रमुख मुद्दे होंगे।

डॉ. अरविन्द सुब्रमण्यिन - भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रा-ट्रीय कृ-ि विज्ञान अकादमी में दिऐ गऐ व्याख्यान का सार

भारतीय कृ-ि का स्वरूप बदलना

1. कृ-ि का क्या महत्व हैः

   कृ-ि के महत्व के कारणों से सभी भलीभांति परिचित हैंः यह बहुत से लोगों को आजीविका, सभी को अनाज, बहुत से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है और कृ-ि क्षेत्र में प्रगति न होने से मुद्रास्फीति बढ़ती है, राजनैतिक और सामाजिक विरक्ति तथा असंतो-ा भी बढ़ता है - इन सभी से अर्थव्यवस्था पिछड़ती है।

   भारत व-र् की कृ-ि नि-पादनशीलता में सुधार के लिऐ आवश्यक 10 अथवा 20 उपायों की सूची देना सरल हैः कृ-ि अनुसंधान और शिक्षा की बिगड़ती हालत पर रोक लगाना तथा संस्थाओं का विस्तार करना, कृ-ि क्षेत्र के लिऐ उदारता बरतना, ड्रिप सिंचाई आदि को प्रोत्साहित करना। किंतु इसकी सूची देना तो सरल है, लेकिन ाायद अनुपयोगी भी। इसका मुख्य कारण है कि जो भी विशे-ाज्ञ किसी सुधार की सिफारिश करते हैं तो हम उनसे एक साधारण प्रश्न पूछते हैं कि 'क्या यह कृ-ि क्षेत्र के लिऐ लाभकारी रहेगा, यदि ऐसा था तो इसे पहले क्यों नहीं लागू किया गया ? प्रश्न अथवा परिकल्पना हैः क्या यह संभव है कि हम अन्य फसलों (सब्जी, दालें) और इन्हें उगाने वाले किसानों की तुलना में अन्य फसलों (अनाज) को वास्तविक रूप से चाहते हैं।

2. सफलताऐं

मैं कृ-ि क्षेत्र की कुछ उपलब्धियों और कमीयों के बारे में बताना चाहूँगा। व-र् 1947 से भारतीय कृ-ि ने एक लंबा सफर तय किया है। हमने खाद्य सुरक्षा में आत्म निर्भरता - कुछ प्रमुख फस्लों में, ग्रामीण निर्धनता दर में पर्याप्त कमी की है, कृ-ि आय में भी वृद्धि हुई है, पौ-िटकता स्तर में भी सुधार हुआ है।

सफलता के क्षेत्र में मैं निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगाः

गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाते हुऐ भारतीय कृ-ि में हरित क्रांति आई है, विशे-ाकर उत्तरी भारत और उसके बाद दक्षिणी भारत में। इसका श्रेय अंतर्रा-ट्रीय अनुसंधान को तो जाता है, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों, कृ-ि वैज्ञानिकों और अनुसंधान कर्ताओं, सार्वजनिक संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अधिक जाता है क्योंकि उन्होंने तकनीक का लिंक वास्तविक अच्छे कृ-ि परिणाम में परिर्वतित किया।

ृवेत क्रांति जिसने भारतीय डेरी क्षेत्र में परिवर्तन किया, इस कारण दुग्ध उत्पादन बढ़ा, आयात पर निर्भरता कम हुई, कृ-ि क्षेत्र से संबंधित संस्थागत संरचनाओं का सृजन किया और उनमें भाग भी लिया तथा डेरी आधारित उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ किया।

उपरोक्त क्षेत्र में सफलताओं के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कि गुजरात में कपास, बिहार में मक्का, उत्तर-प्रदेश में चीनी, मध्य-प्रदेश में गेहूं और पश्चिम बंगाल में आलू।

3. सभी कुछ अच्छा नहीं है

इतनी सफलताऐं प्राप्त करने के बाद भी हमें कई समस्याओं का समाधान करना है। अपने दावे के समर्थन में मैं 2 उदाहरण प्रस्तुत करता हूँः भारत की समग्र कृ-ि कामगार उत्पादकता चीन से दो-तिहाई और सीमांत देशों से 1 प्रतिशत के लगभग कम है। भूमि उत्पादकता (प्रति एकड़ फसल के रूप में) भी सीमांत देशों से काफी कम है। उदाहरण के लिऐ भारत में चावल की उत्पादकता चीन की तुलना में 50 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में एक-तिहाई है।

फिगर 1. समग्र कृ-ि उत्पादकताः सीमांत देशों से अभी भी काफी कम है।

दूसरा, कृ-ि आय (सिंचाई, ुद्ध-लागत और स्थानीय बाजार की दरों पर नहीं बेचे गऐ उत्पादों का मूल्य) अभी भी काफी कम है। एक मध्यम किसान परिवार की ुद्ध व-र् 2012-13

में रू. 19,250 के लगभग थी अथवा प्रति माह रू. 1,600 थी, यह आय निर्धन रेखा से बहुत अधिक नहीं है। निःसंदेह कई भिन्नताऐं हो सकती हैं लेकिन सच यह है कि भारत में किसान बनना लाभकारी नहीं है।

फिगर 2. कृ-ि परिवारों की आय।

4. नई चुनौतियां

कई नई और गंभीर चुनौतियां हैंः 4 प्रमुख कृ-ि संसाधन हैंः वातवरण, पानी, भूमि और भूमि की गुणवत्ता, इन सभी क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन से कृ-ि उत्पादकता कम होगी और फसलों की किस्मों में वृद्धि होगी (इन सभी का भारतीय कृ-ि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है); जलवायु परिवर्तन से पानी की कमी हो रही है और इसका कारण कृ-ि क्षेत्र में अत्यधिक उपयोग तथा घरों में दुरूपयोग, विशे-ाकर हरियाणा और पंजाब में भूमि की गुणवत्ता न-ट हो रही है तथा जनसंख्या बढ़ने के कारण भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इस भूमि का अन्य क्षेत्रों में उपयोग लाभकारी सिद्ध हो रहा है।

5. (क) अनाज पर निर्भरता

हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं, लेकिन यह लाभ केवल उन किसानों को मिल पाता है जो बाजार में बेचने योग्य फसलें उगाते हैं और यह लाभ केवल मोटे अनाजों और गेहूं पर ही मिलता है। इसका लाभ भी कुछ ही राज्यों को मिलता है, जैसे कि उत्तर-भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य।

इसके बाद हम बिजली, पानी, खाद (अब दूसरी सबसे बढ़ी आर्थिक सहायता वाली वस्तु), बीज, ऋण, हम कृ-ि आय को आयकर से मुक्त रखते हैं और समय-समय पर कर्ज माफी दे रहे हैं।

5. (ख) छोटे किसानों को नहीं बल्कि बड़े किसानों को

आर्थिक सहायता का लाभ न केवल अनाज उगाने वाले किसानों को मिलता है, बल्कि यह बड़े किसानों को भी मिलता है, अथवा यह छोटे किसानों तक तो पर्याप्त रूप से पहुंच ही नहीं पाता।

कई उदाहरणः परिभा-िक रूप से कृ-ि आय में छूट केवल उन बड़े किसानों को मिलती है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। खाद पर आर्थिक सहायता का लाभ केवल छोटे और मझौले किसानों को तो एक-तिहाई भाग ही मिलता है, बाकी सारा लाभ बड़े किसानों को जाता है। कृ-ि ऋण की राशि देखने से भी पता चलता है कि सारा पैसा केवल किसानों को ही नही दिया जाता। कर्ज माफी के क्षेत्र में भी यह आश्चर्यजनक है कि छोटे और मझौले किसान औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से कम राशि का ऋण लेते हैं और सबसे अधिक ऋण वे अनौपचारिक साधनों से प्राप्त करते हैं। जबकि बड़े-बड़े किसान 75 प्रतिशत ऋण ले लेते हैं, बिजली के क्षेत्र में आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि इसका लाभ निम्न वर्ग के किसानों को केवल 10 प्रतिशत मिलता है और बड़े-बड़े किसानों को इसका आर्थिक लाभ 37 प्रतिशत तक अधिक होता है, क्योंकि वे अत्यधिक मात्रा में बिजली का उपभोग करते हैं।

6. कुछ फस्लों को कम महत्व देते हैं

यदि हम कुछ फस्लों को अत्यधिक महत्व देंगे तो अधिकतम फस्लों को कम महत्व देना पड़ेगा। यहां पर में दालों, डेरी और पशुधन, फल और सब्जियों तथा तिलहनों का उदाहरण देता हूँ।

दालों के मामले में इनका समर्थन मूल्य बढ़ाया जाता है (बिना खरीद के न्यूनतम समर्थन मूल्य, यहां पर ध्यान देना होगा कि किसानों को इसका बहुत कम लाभ मिलता है) और इस खरीफ मौसम मैं इसके उत्पादन में 20 लाख टन की वृद्धि हुई है (कुल 87 लाख मैट्रिक टन उत्पादन में से)। इसके पश्चात भी यह अनुमान है कि कुल तुर उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत भाग घो-ित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बेचा गया है, जिस कारण दाल उत्पादकों को लाभ नहीं मिला। माल रखने की सीमा और निर्यात प्रतिबंध के कारण बाजार भाव निचे रहे, यदि उन्होंने किसानों का ध्यान रखा होता तो किसानों का भाग्य संवर सकता था।

यह एक महत्वपूर्ण धारणा है कि किसान और ृाक्तिशाली मध्यमवर्ग के उपभोक्ता के हितों के बीच टकराव है। इससे संकट उत्पन्न होता है जिस कारण सरकारी नीतियों से कृ-ि वस्तुओं के मूल्य अस्थिर रहते हैं और कडी मेहनत करने वाले किसानों को अपनी फसल के मूल्य की अनिश्चितता बनी रहती है। अतः जब उपभोक्ता मूल्य बढते हैं तो आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। किंतु इस धारणा और इसके बाद नीति परिवर्तन करके किसानों के मूल हितों की रक्षा नहीं हो पाती। यदि आज किसान को कम मूल्य मिलेगा तो आने वाले समय में कृ-ि उत्पादन में कमी आऐगी (विशे-ाकर उन फस्लों के उत्पादन में जिनका आमतौर पर अधिक मात्रा में घरेलू उत्पादन किया जा रहा है, जैसे दालें, फल एवम् सब्जियां) और इसका परिणाम होगा की आने वाले समय में उपभोक्ता मूल्य बढ़ जाऐगा। इस प्रकार नि-क-र्ा यह

है कि एक सही योजना और राजनैतिक वातावरण बनाने से किसान भी और उपभोक्ता दोनों को लाभ हो सकता है।

फल एवम् सब्जियों की बिक्री पर कृ-ि उत्पाद विपणन समितियों के माध्यम से प्रतिबंध लगाने से हानि हो रही है। अब सरकार ने एक इलेक्ट्रोनिक कॉमन मॉर्केट ाुरू की है जिसके परिणामों की प्रतिक्षा है।

डेरी और पशुधन के मामले में यह जानना होगा की पशुधन किसानों की आर्थिक स्थिति उनके पास रखे हुऐ पशुधन के वास्तिविक मूल्य पर निर्भर करेगी और वैसे ही पशुओं से प्राप्त होने वाले लाभ के भाग्य और भवि-य का निर्णय होगा। किंतु अभी तक पशुधन का क्षेत्र लाभकारी नजर नहीं आता। यहां में उल्लेख करना चाहूँगा की भारतीय उपभोक्ताओं का प्रोटीन पर महत्व बढ़ता जा रहा है। भारत के लोगों में पौ-िटक आहार की कमी से उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। उनके स्वास्थ्य को बचाने के लिऐ अनाज पर निर्भरता कम करके प्रोटन वाली फस्लों को महत्व देना होगा, जैसे की दालें, डेरी उत्पाद और पशुधन।

अंत में मैं तकनीकी पर विशे-ा बल देना चाहूँगा जो न केवल दालों, तिलहनों के लिऐ महत्वपूर्ण है बल्कि डेरी उत्पादों के लिऐ भी। किसानों को भी नई तकनीक का लाभ वैसे ही पहुंचाया जाऐ जैसा कि अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को पहुंचाया जा रहा है।

7. नि-कर्-ा

फस्लों की 2 किस्मों के बीच के असंतुलन को कैसे दूर किया जा सकता है ?

जिन फस्लों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, इस संबंध में यह एक बडी चुनौती है कि सरकार या राजनैतिक रूप से उन फस्लों पर दी जा रही आर्थिक सहायता के वर्तमान स्तर को कम कर दे। यह लगभग असंभव होगा। इसकी एकमात्र संभावना है कि समर्थन की मात्रा बनी रहे किंतु इसके स्वरूप को बदलकर इसे प्रोत्साहन के रूप में दिया जाऐ। मेरा मानना है कि यदि दी जा रही आर्थिक सहायता के इन 3 रूपों को बदलकर प्रत्यक्ष सहायता के रूप में अपना लिया जाऐ तो यह राशि कम होकर लगभग रू. 1 लाख वार्-िक प्रति किसान तक हो सकती है, जिससे सरकारी राजस्व पर भी कम बोझ पड़ेगा।